(b) No. According to the same source, foodgrains production in U.S.A. and India in 1992 was of the order of 355 million tonnes and 212 million tonnes (with rice considered in terms of paddy) respectively.

(c) The difference is due to high level of mechanisation and productivity in U.S.A.

(d) Diversification of agriculture and development of secondary and territory is expected to ease the pressure of population on land.

Central Assistance for Rehabilitation

7115. **SHRIMATI BASANTI SHARMA:** Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Government of Assam has submitted a request for seeking Central Assistance for rehabilitatoin and to make up for the losses suffered due to floods in the State;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the amount sanctioned for the purpose and the amount actually released so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

पठार विकास परियोजना के अधीन योजनायें

7116. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनंदन जैन**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में विश्व-बैंक द्वारा वित्त पोषित पठार विकास परियोजनाओं के अधीन विभिन्न योजनाओं के संचालन और रख-रखाव का खर्च आदिवासियों से वसूल किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विशेषकर किन-किन परियोजनाओं के संबंध में "लागत की वापसी" के सिद्धान्त को अपनाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) विश्व बैंक द्वारा अपनी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से देश में चलाई जा रही कृषि और ग्रामीण विकास परियोजनाओं/योजनाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि लगभग सभी योजनाएं अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है और क्या सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई सर्वेक्षण किया है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार): (क) जी, हां।

परियोजना में, बिहार सरकार तथा परियोजना के लाभानुभोगियों के बीच लागत और लाभ की हिस्सेदारी के लिए सहमत व्यवस्था के माध्यम से लागत की कुछ राशि की वसूली का प्रावधान हैं।

(ख) लागत की वसूली के कारणों में निम्न बातें शामिल हैं :-

(1) लाभानुभोगियों को कार्यकलापों तथा उनके स्थानों के चयन सहित परियोजना आयोजन प्रक्रिया में शामिल करना, तथा (2) लाभानुभोगी इनमें से कुछ परिसम्पत्तियों के स्वामी हों और उनका उपयोग करें।

(ग) परियोजना लाभानुभोगियों के साथ लागत की हिस्सेदारी की व्यवस्थाएं इन क्षेत्रों में चलाने का प्रस्ताव है- (1) सिंचाई स्कीमें (2) जल संग्रहण टैंक/खुदे हुए कुएं, (3) पीने के पानी की सुविधाएं, (4) पनधारा उपचार आदि।

(च) इस समय कृषि-क्षेत्र में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त 12 परियोजनाएं चल रही हैं।

(ङ) और (च) आमतौर पर, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाओं का उद्देश्य आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाना, अनुसंधान और सुपुर्दगी प्रणालियों की गुणवत्ता में सुधार करना, आदान सहायता को बढ़ाना आदि होता है। ये उद्देश्य कमोबेश विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पूरे किए गए हैं। परियोजना क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों पर किए जाने वाले विभिन्न मॉनिटरिंग मूल्यांकन सर्वेक्षणों, मध्यावधि समीक्षाओं तथा परियोजना पूरी होने संबंधी रिपोर्टों से उक्त तथ्यों का पता चला है।

पशु-पालन-विकास के लिए योजनायें

7117. **श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान गुजरात सरकार द्वारा पशुपालन विकास हेतु कौन-कौन सी योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं?

(ख) कौन-कौन से जिलों में ऐसी योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेतराम): (क) और (ख) विभिन्न राजकीय योजनाओं के अतिरिक्त 1993-94 के दौरान गुजरात सरकार को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए निधियां निर्मुक्त की गई थीं और इन योजनाओं को राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित किया जाना था:

(1) राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम . . .	(188.00 लाख रुपए)
(2) राष्ट्रीय पशु-प्लेग उन्मूलन सहितपशुधन स्वास्थ्य सुविधा	(178.61 लाख रुपए)
(3) पशु शव उपयोगिता केन्द्र तथा निस्त्वचन एककों की स्थापना	(25.28 लाख रुपए)
(4) भारवाही पशुओं का विकास . . .	(11.15 लाख रुपए)
(5) राष्ट्रीय मेढ़ा/मृग उत्पादन कार्यक्रम . . .	(15.00 लाख रुपए)
(6) हिमित-वीर्य प्रौद्योगिकी का विस्तार . .	(1.20 लाख रुपए)
(7) प्रमुख पशुधन उत्पादन के अनुज्ञान के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	(20.00 लाख रुपए)

Experiments on Animals for Medical Research

7118. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is multiplicity of medical reserach involving torturous experiments on animal life;

(b) whether it is also a fact that such experiments are also carried on in cosmetic and non-essential industry; and

(c) if so, what steps Government propose to ban such experiments in at least non-essential industries?